(d) the concerned State Electricity Board is the deciding authority.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा सहायता में कटौती

771. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) इस कटौती का आर्थिक स्थिति तथा चालू योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) हाल ही में, भारत और चीन जैसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से संबंधित सहायता को कम करने के संबंध में इस आधार पर विचार-विमर्श हुआ है कि ये देश निजी निवेश को आकर्षित कर सकते है। तथापि, इस पर विपरीत तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार की निजी निधियां गरीबी कम करने/सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को वित्त पोषित नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के समर्थन का मर्म गरीबी हटाने और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों से संबंधित है, भारत का पक्ष मजबूत होता है। तथापि, इस प्रकार के मामले केवल विचार-विमर्श तक ही है और किसी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचे है।

फिर भी, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित लेख "भारत:देश सहायता योजना" के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत के लिए आई डी ए/वां चक्र (वित्तीय वर्ष 93-95) के दौरान तीन वर्षीय ऋपाद कार्यक्रम 3.47 बिलियन अमरीकी डालर का था। आई डी ए/वे चक्र (वित्तीय वर्ष 96-98) के दौरान पूर्वानुमानित ऋपाद कार्यक्रम 3.6 बिलियन अमरीकी डालर का है।

Excise duty evasion by Reliance Industries

772. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 508 given in Rajya Sabha on the 3rd May, 1994 and State:

(a) the details of progress made in the case at Serial No. 3 of the statement annexed to the question under reference;

(b) the progress made in regard to the other cases stated in the said statement;

(c) the action taken by Government thereon;

(d) whether Central Excise and Customs Adjudicating Tribunal is taking unduly long periods in finalising the cases;

(e) if so, steps taken by Government; and

(f) the number of cases pending with CEGAT as on date; since when are they pending with it and by what time are these likely to be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) (a) In the case referred to in the question a demand for Rs. 1.09 crores was confirmed vide adjudicating order dated 25.5.1993. A penalty of Rs. 25 lakhs and a fine of Rs. 10 lakhs in lieu of confiscation of plant and machinery were imposed on M/S Reliance Industries Ltd. (RIL). M/s RIL have deposited Rs. 10 lakhs and executed a Bank guarantee for Rs. 25 lakh in terms of stay order passed by Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (CEGAT). The appeal is still pending before the Tribunal.

(b) and (c) Information is given in the enclosed statement *(See* below).

(d) to (f) 52,366 appeals were pending with CEGAT as on 1.11.1995 and the oldest case pertains to year 1976. To reduce the number of pending cases, vacant posts of Members arc being filled up and legislative change for expediting disposal has been introduced as per the Finance Act, 1995. However, no time frame can be laid regarding finalisation of the cases as old cases are pending mainly due to stay granted by the courts.